



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii),  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 92]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 4, 1981/फाल्गुन 13, 1902

No. 92]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 4, 1981/PHALGUNA 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के  
रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1981

क्र. आ. 144 (अ).—केंद्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आवेश सं. का. आ. 128 (अ)/18 चक/18 कक/उ. वि. वि. अ. /73, तारीख 5 मार्च, 1973 द्वारा व्यक्तियों के एक निकाय को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), मेसर्स कृष्णा सिनिकोट एंड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का सम्पूर्ण प्रबंध 5 मार्च, 1973 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आवेश सं. का. आ. 146 (अ)/18 चक/18 कक/उ. वि. वि. अ. /78, तारीख 3 मार्च, 1978 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का, 5 मार्च, 1978 से दो वर्ष की अवधि के लिए, प्रबंध करने रहने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और केंद्रीय सरकार ने, यह राय होने पर कि सर्व साधारण के हित में यह समीचीन है कि प्राधिकृत व्यक्ति पूर्वोक्त सात वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध करना जारी रखे, उद्योग (विकास और

विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन एक आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को किया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ऐसा प्रबंध एक वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जाए ;

और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 29 फरवरी, 1980 के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध दो वर्ष की अवधि तक जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर दिया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आवेश सं. का. आ. 145 (अ)/18 चक/18 कक/उ. वि. वि. अ. /80, तारीख 5 मार्च 1980 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का 5 मार्च, 1980 से एक वर्ष की अवधि के लिए, प्रबंध करने रहने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18 चक के साथ पठित धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत व्यक्ति को निदेश देती है कि वह 5 मार्च, 1981 से आरम्भ होने वाली 6 मास की अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध करना जारी रखे ।

[फा. सं. 2(1)/80-सी.यू.एस.]

आर. एन. चोपड़ा, अपर सचिव

**MINISTRY OF INDUSTRY****(Department of Industrial Development)****ORDER**

New Delhi, the 4th March, 1981

**S.O. 144(E).**—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 128(E)/18FA/18AA/IDRA/73, dated the 5th March, 1973, the Central Government had authorised a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, for a period of five years from the 5th March, 1973;

And whereas the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 146(E)/18FA/18AA/IDRA/78, dated the 3rd March, 1978, authorised the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of two years from the 5th March, 1978;

And whereas the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interests of general public that the authorised person should continue to manage the said

industrial undertaking after the expiry of the period of seven years aforesaid, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period of one year;

And whereas the said High Court, by its Order dated the 29th February, 1980, permitted the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of two years;

And whereas the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 145(E)/18FA/18AA/IDRA/80 dated the 5th March, 1980, authorised the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year from the 5th March, 1980;

And now in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA, read with section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of six months commencing from the 5th March, 1981.

[F. No. 2(1)/80-Cus.]

R. N. CHOPRA, Addl. Secy.